रहा है सब जगहों में, तो कोई खामियी नहीं है कि वे पत्रकार उसी समूह के किसी तरह से छांट दिये जायें। और

(3) यह मैं चाहूंगा कि सरकार इंक्वायरी करके सदन में एक बयान दे कि क्यों इस तरह से हुआ? नहीं तो आज नव-भारत टाइम्स के साथ हुआ है, कल जनसत्ता के साथ होगा, परसों टाइम्स आफ इंडिया के साथ होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाये और पत्रकारों के जीवन के साथ, उनकी अस्मिता के साथ, उनके विचारों के साथ जो इस तरह से खिलवाड़ किया जाता है, इसको तत्काल रोका जाना चाहिये। धन्यवाद।

5 P.M.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदया, ढाई वर्ष पूर्व लखनऊ से नवभारत टाइम्स का जो हिन्दी संस्करण निकलता था, वह भी इसी तरीके से बन्द कर दिया गया। तो मेरा निवेदन यह है कि शकर दयाल सिंह जी ने जो विषय उठाया है उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूं।

उपसभापति : पढ़ते नहीं हैं लोग हिन्दी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हमारे लोक-तंत्र में जो पत्रकारिता है, पत्रकार एक चौथे स्तंभ हैं। संगमा जी यहां पर मौजूद हैं। लखनऊ के बारे में उनको जानकारी है। मैं कई बार उनको इस संबंध में लिख भी चुका हूं। पटना का नवभारत टाइम्स का जो हिन्दी संस्करण है तथा जो लखनऊ का भी है, इस सारे मामले को इस परिपेक्ष्य में देखें।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश) : मैं भी इससे अपने को संबद्ध करना चाहता हूं। जयपुर से भी जो संस्करण निकलता था, उसमें भी इसी तरह हुआ। लखनऊ में भी यह हुआ है। यह जो भाषाई हमारे पत्रकार हैं, यह उनकी अवहेलना है। जिस प्रकार की स्वतंत्र पत्रकारिता हम चाहते हैं, मैं समझता हूं उसके साथ भी यह मजाक किया जा रहा है।

MINE BLASTS L\ JAMMU AND KASHMIR

श्री कृष्णलाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अभी बीस तारीख को जो एक गंभीर घटना जम्मू-कश्मीर में हुई, उस ओर दिलाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्र उड़ी का वह इलाका है जहां माईन ब्लास्ट हुआ है, जिसमें आर्मी के 10 जवान मरे हैं। पिछले कई वर्षों में यह एक अपवाद है कि एक सीनियर आर्मी आफिसर ब्रिगेडियर रैंक का, वह भी इसमें मरा है। इसमें दो नागरिक भी मरे हैं। इससे पहले राजौरी पुंछ के सीमावर्ती इलाके में माईन ब्लास्ट हुए हैं। अब जो वहां पर इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, वह दो परस्परविरोधी बातें सरकार देश के सामने ला रही है। इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आना चाहिये। वहां बोर्डर एरियाज में माईन ब्लास्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमारी सीमाओं पर छेड़छाड़ की जा रही है। वहां आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, आर्म्स भेजे जा रहे हैं और ट्रेंड लोग भेजे जा रहे हैं। अब जम्मू में बम ब्लास्ट फ्रीक्वेंटली होने लग गये हैं। इसी के साथ डोडा जिले में, किश्तवार जिले में हत्यायें हो रही हैं और श्रीनगर में नार्मल लाईफ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में बार-बार यह संकेत होता है कि हम वहां पर इलेक्शन कराने वाले हैं। यह जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि गृह मंत्री जी ने अपोजिशन के साथ एक वार्तालाप शुरू किया कि कश्मीर के बारे में चर्चा करें। तो मैं सबसे पहले गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू-कश्मीर एफ्फेयर्स अब उनके अन्तर्गत है, उनकी मिनिस्ट्री के अन्तर्गत है या नहीं है? क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर एफ्फेयर्स का सारा काम अब पी.एम.ओ. के पास है। हमें एक रिपोर्ट में बताया गया कि जम्मू-कश्मीर के बारे में कोई भी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री इसलिये देने को तैयार नहीं है क्योंकि अब यह डिपार्टमेंट पी.एम.ओ. के पास है। परन्तु जब बातचीत करनी है तो वह होम मिनिस्टर कर रहे हैं। यह एक कंफ्यूजन गवर्नमेंट में ही है कि जम्मू-कश्मीर का वारिश कौन है – पी.एम.ओ. है या होम

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

मिनिस्ट्री है ? इतनी क्रूशियल और सेंसेटिव सिचुएशन में इनके अन्दर भी न कोई कोआर्डिनेशन है और न किसी प्रकार का तालमेल है। तो ऐसी स्थिति में जम्मू-कश्मीर की क्या हालत होगी ? वहां पर माइग्रेंट्स की कोई व्यवस्था नहीं है । अभी तक डी-लिमिटेशन हुआ नहीं है और रोज वहां के लिये चुनाव की बात होती है । मुझे यह कहना है कि सबसे पहले यह बताया जाये कि जो माईन ब्लास्ट हुए हैं, गवर्नर पर अटैक हुआ है, 26 जनवरी को टाईम बम ब्लास्ट हुए हैं, यह सारी जो घटनायें हो रही हैं, तो क्या इसके बारे में सरकार आंखें और कान बन्द करके बैठी हुई है ? क्या इसकी तरफ कोई कदम उठाया जा रहा है और इस कदम से कोई नतीजा निकल रहा है और इस नतीजे से क्या सरकार यह विश्वास के साथ कह सकती है कि अब हमने जम्मू-कश्मीर में ऐसी हालत पैदा कर दी है कि हम वहां शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वायत्त चुनाव करवा सकते हैं? ऐसी स्थिति में मुझे यह कहना है कि हमें पाकिस्तान को चेतावनी देनी होगी, क्योंकि वह जम्मू-कश्मीर में टांग अड़ा रहा है। हम यह चाहते हैं कि वहां पर लोकतंत्र प्रक्रिया जल्दी शुरू हो । परन्तु पाकिस्तान इस रास्ते में रुकावटें डाल रहा है । इस चीज को हमें जितना जोर से उठाना चाहिये वह नहीं उठा रहे हैं । हमें एक बात पूरे जोर से कहनी चाहिये कि जब तक वहां स्थिति नार्मल नहीं होती वहां चुनाव की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। यह संकेत हमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेविल पर ही देना चाहिये क्योंकि सबकी चिंता है कि जम्मू-कश्मीर में सिचुएशन नार्मल हो और उसके बाद ही वहां पर चुनाव हों । हम इस बात को पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं कि हम सैल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत नहीं मानते । चुनाव वहीं पर रेग्युलरली हो रहे हैं, अब भी होंगे और वही इसका उत्तर होंगे कि जम्मू-कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं ।

एक बात थोड़ी सी और कह कर मैं समाप्त करूंगा कि हमने पिछले 1994 के बजट सेशन के ओपनिंग डे पर एक रिजोल्यूशन पास किया था दोनों हाऊसेज में और वह सर्वसम्मत रिजोल्यूशन था कि हमारी सरकार को यह कहा गया था कि वह पाक आक्यूपाइड कश्मीर को खाली कराने के लिये कदम उठाये । मैं चाहूंगा कि सरकार इसके बारे में एक स्टेटमेंट दे कि एक साल के अन्दर जो हमने दोनों हाऊसेज में प्रस्ताव पारित किये थे, उसके बारे में सरकार ने उसको पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये हैं और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि अगर सरकार उस दिशा में कदम उठाती तो वहां मिलिटेंसी खत्म हो जाती और वहां की स्थिति भी नार्मल हो जाती । पाकिस्तान के हौसले इसलिये बढ़ रहे हैं कि हमारा जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उस पर दबाव डाल कर उसे वापस लेने के लिये हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिये । तभी कश्मीर के अन्दर हिंसा खत्म होगी, हत्यायें खत्म होंगी, ब्लास्ट खत्म होंगे, नार्मल सिचुएशन होगी और इस सिचुएशन को हम प्राप्त करके आगे चुनाव के बारे में सोच सकेंगे और हमें यह बात निश्चित करनी है कि पहले हम स्थिति नार्मल करेंगे और फिर चुनाव कराएंगे । यही बात मैं कहना चाहता था, मैंने कहा है, आपने सुना, धन्यवाद ।

ACUTE DRINKING WATER SCARCITY IN VILLAGES OF MAHARASHTRA

डा० दापू काळदाते (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि गए एक सप्ताह से मैं जिस विशेष उल्लेख को लाने की कोशिश कर रहा था, आज कम से कम मुझे आपके द्वारा सफलता मिली । क्योंकि यह महाराष्ट्र की हद तक एक अति गंभीर मामला हुआ है । इस साल महाराष्ट्र में औसतन हर साल के मुकाबले में पचास फीसदी पानी कम गिरा है और इसका एक परिणाम यह हो गया है कि आज महाराष्ट्र में, खासकर मैं जिस इलाके से आता हूं, इस इलाके में सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 5776 गांवों में पानी मिलना दुश्वार है । अति कम है पानी और रोज मेरे पास तो कई अखबार पड़े हुए हैं, इससे लगता है कि टैंकर से पानी देने का काम शुरू हो गया है । मैंने नवम्बर में इस